[2018] 3 एस. सी. आर. 551

तमिल नाडू मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 196)

में

(2018 का आई. ए. सं. 33686)

अप्रैल 24, 2018

▌ दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. के. सिकरी, ए. एम. खानविलकर,

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, जे. जे.▐

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, *2000:*

विनियम *9*- विनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिका- विनियम के प्रावधानों पर दिनेश सिंह चौहान मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था- मामला * दिनेश सिंह चौहान मामले पर पुनर्विचार के लिए संविधान पीठ को भेजा गया था। विनियमन के संचालन की मांग इस हद तक की गई है कि यह प्रावधान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए राज्यों को प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने से प्रतिबंधित करता हुआ माना गया है - राज्य सरकार को शैक्षणिक वर्ष *2018-19* के लिये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवाकालीन उम्मीदवारों को प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की अपनी नीति को लागू करने की अनुमति देने के लिए निर्देश मांगा गया है। -अंतरिम राहत को भी संविधान पीठ को

प्रेषित किया गया- अंतरिम राहत पर विचार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया- दिनेश सिंह चौहान मामले ने संविधान पीठ के फैसलों पर उचित ध्यान देने के बाद विनियमन *9 (iv)* में प्रावधान का अर्थ लगाया था- दिनेश सिंह चौहान मामले में निर्णय अभी भी मैदान में हैं और अंतरिम राहत तय करने के चरण में उन्हें दरकिनार नहीं किया ज– ा सकता है इस स्तर पर अंतरिम राहत एक अनिवार्य अंतिम आदेश के बराबर हो और इसलिए इनकार कर दिया गया-अंतर्वर्ती आदेश।

* उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दिनेश सिंह चौहान (2016) 9 एससीसी 749: [2016] 6 एस.सी.आर. 571; आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य [1964] 6 एस. सी. आर. 368; कुमारी चित्रा घोष बनाम भारत संघ (1969) 2 एस.सी.सी. 228: [1970] 1 एस. सी. आर. 413; मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2016) 7 एस. सी. सी. 353; के. दुरैसामी बनाम तमिलनाडु राज्य (2001) 2 एससीसी 538: [2001] 1 एस. सी. आर. 490; ए. आई. आई. एम. एस. एस. छात्र संघ बनाम ए. आई. आई. एम. एस. (2002) 1 एस.सी.सी. 428: [2001] 2 पूरक एस. सी. आर. 79; मध्य प्रदेश राज्य बनाम गोपाल डी तीर्थानी (2003) 7 एस.सी.सी. 83: [2003] 1 पूरक एस.सी.आर. 797; सुधीर एन. बनाम. केरल राज्य (2015) 6 एस.सी.सी. 685 [2015] 1 एस.सी.आर. 884; डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1999) 7 एस सी सी 120: [1999] 1 पूरक एस.सी.आर. 249 -संदर्भित किया गया।

मामलें संदर्भ किये गए-

[2016] 6 एस. सी. आर. 571	संदर्भित किया गया है	पैरा 1
[1964] 6 एस. सी. आर. 368	संदर्भित किया गया है	पैरा 2
[1970] 1 एस. सी. आर. 413	संदर्भित किया गया है	पैरा 2

(2016) 7 एस. सी. सी. 353	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[2001] 1 एस.सी.आर. 490	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[2001]2 पूरक एस.सी.आर. 79	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[2003]1 पूरक एस.सी.आर. 797	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
[2015] 1 एस. सी. आर. 884	संदर्भित किया गया है	पैरा 13

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में 2018 का आई. ए. सं. 33686

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के साथ

2018 की रिट याचिका (सी) सं 252, 295 और 293

अमन लेखी, ए.एस.जी., अरविंद दातार, केवी विश्वनाथन, ए. के. सिन्हा, विकास सिंह, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव, समन अहसान, आयुष जैन, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, जोस अब्राहम, हरीश पांडे, डॉ. निशीश शर्मा, शरद कुमार सिंघानिया, रोहित भट, गुरमीत सिंह मक्कर, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, अमनदीप कौर आहूजा, अभिषेक, सुश्री दीपिका कालिया, सुश्री सृष्टि बनर्जी, के. वी. विजयकुमार, सुश्री मैत्रेयी मिश्रा, तपेश कुमार। सिंह, मो. वकास, आदित्य प्रताप सिंह, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंक वी. एल., सुश्री. विजय मोहन वी., अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का आदेश इनके द्वारा दिया गया था-

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दिनेश सिंह चौहान (2016) 9 एससीसी 749 में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गये निर्णय ने भारतीय चिकित्सा परिषद स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के विनियम विनियम 2000 यथा 15 फरवरी 2012 को संशोधित, के विनियम 9 (IV) और 9 (VII) के प्रावधानों का अर्थ लगाया। वर्तमान मामलों के समूह में, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने, 13 अप्रैल 2018 के एक आदेश द्वारा, राय दी कि इन याचिकाओं पर एक बड़ी पीठ द्वारा विचार करने की आवश्यकता है।

2. इस संदर्भ को बनाने में, संदर्भ आदेश ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों का संकेत दियाः

(i) दिनेश सिंह चौहान के निर्णय में सातवीं अनुसूची की विधायी सूचियों में प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया गया है, विशेष रूप से संघ सूची की प्रविष्टि 66 और समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 पर;

(ii) याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण संघ के अनन्य क्षेत्र (प्रविष्टि 66 सूची I) के अंतर्गत आता है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25 सूची III) में एक विषय है। हालाँकि, सूची III की प्रविष्टि 25 सूची I की प्रविष्टि 66 के अधीन है, राज्य को स्नातकोत्तर

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के तरीके और विधि पर कानून बनाना अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया गया है;

(iii) याचिकाओं के वर्तमान समूह में जो तर्क उठाए गए हैं, उन्हें इस न्यायालय के समक्ष दिनेश सिंह चौहान मामले में संबोधित नहीं किया गया था।;

(iv) दिनेश सिंह चौहान मामले में निर्णय आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य , कुमारी चित्रा घोष बनाम भारत संघ और मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य में संविधान पीठ के तीन फैसलों पर विचार नहीं करता है; और

(v) न्यायपीठों द्वारा समान शक्ति के निर्णय लिए जाते हैं जैसा कि दिनेश सिंह चौहान में किया।

3. एक बड़ी पीठ का संदर्भ देते हुए, निर्देश/आदेश में कहा गया कि "यह उचित होगा कि अंतरिम राहत पर भी बड़ी पीठ द्वारा विचार किया जाए।" तदनुसार, विद्वान मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर, अंतरिम राहत के प्रश्न पर विचार करने के लिए कार्यवाही को संविधान पीठ के समक्ष रखा गया है।

4. हमने याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार और श्री केवी विश्वनाथन, श्री अमन लेखी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री ए. के. सिन्हा, उत्तरदाता भारत संघ के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील-, श्री विकास सिंह विद्वान वरिष्ठ वकील एम.सीआ.ई. के लिए और श्री वी. गिरि, तमिलनाडु राज्य के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है।

5. तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ भारत में, निम्नलिखित राहत की मांग की गई हैः

"(क) परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त लिखित/आदेश/निर्देश को जारी करके घोषित करें कि स्नातकोत्तर का विनियम 9 चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 {विशेष रूप से, विनियम 9 (iv) और 9 (vii)} इच्छुक सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश प्रदान करने के प्रविष्टि 25 सूची III के अंतर्गत राज्य को शक्ति से वंचित नहीं कर सकता है;

(ख) वैकल्पिक रूप से, यदि स्नातकोत्तर चिकित्सा का विनियम 9 समझा जाता है कि विनियम, 2000 राज्यों को डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की अनुमति नहीं देने वाला लगता है, तो परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट / आदेश/ निर्देश, विनियम जारी करके विनियम 9 (विशेष रूप से, विनियम 9 (iv) और 9 (vii) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करने वाला और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत भी माना जाने की घोषणा करें।"

6. अंतरिम प्रार्थना यह है कि इस न्यायालय को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम 2000 के विनियम 9 के संचालन पर इस हद तक कि यह माना जाता है कि यह राज्यों को स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के सेवाकालीन इच्छुक उम्मीदवारों को प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने से रोकता है, रोक लगा देनी चाहिए, । स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम। तमिलनाडु राज्य को शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का स्रोत एक अलग व्यवस्था प्रदान करने की अपनी नीति को लागू करने की अनुमति देने के लिए एक निर्देश मांगा गया है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि 1989 से - इन-सर्विस उम्मीदवारों डिग्री पाठ्यक्रमों में राज्य की 50 प्रतिशत सीटें को प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने की तमिलनाडु राज्य की एक नीति रही है। इसके अलावा, 2007 से तमिलनाडु राज्य ने एक सरकारी आदेश द्वारा, ग्रामीण, पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में सेवा देने वाले इन-सर्विस उम्मीदवारों को वेटेज वरीयता प्रदान की है। यह नीति सरकारी अस्पतालों में विशेष रूप से ग्रामीण, पहाड़ी और कठिन स्थानों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। इस पृष्ठभूमि में निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया गया हैः

(i) हालांकि, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 ("शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित") राज्य सूची I की प्रविष्टि 66 ("उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों में मानकों का समन्वय और निर्धारण") के प्रावधानों के अधीन है, राज्य को स्नातकोत्तर

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के तरीके या विधि निर्धारित करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है।

(ii) आर. चित्रलेखा, कुमारी चित्रा घोष और मॉडर्न डेंटल कॉलेज (ऊपर) में इस न्यायालय के तीन संविधान पीठ के फैसलों द्वारा सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के बीच के संबंध पर विचार किया गया है;

(iii) के दुरैसामी बनाम तमिलनाडु राज्य , एम्स छात्र संघ बनाम एम्स और मध्य प्रदेश राज्य बनाम गोपाल डी तीर्थानी के मामले में अपने निर्णयों में, इस न्यायालय ने राज्य सरकारों के डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों का एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के अधिकार को बरकरार रखा है, जिसमें व्यक्तियों के एक परिभाषित वर्ग के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग वैध माना गया है जब तक यह एक वैध वर्गीकरण पर आधारित है;

(iv) सरकारी और अन्य सेवाओं में कार्यरत डॉक्टरों के बीच वर्गीकरण उचित है और इसका संबंध सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है; और

(v) दिनेश सिन्ह चौहान **9** में विनियम 9 पर दी गई व्याख्या, कि सेवाकालेन इच्छुक उम्मेदवारों के लिये स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं है क्योंकि यह विनियमन 9 (VII) के तहत केवल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान किया गया है, में निम्नलिखित कारणों से पुनर्विचार की आवश्यकता है:

(1) सूची III की प्रविष्टि 25 के तहत राज्य को इन-सर्विस उम्मीदवारों को प्रवेश का एक अलग चैनल प्रदान करना प्रतिबंधित करने के लिये विनियम 9 में कोई स्पष्ट या निहित बाधा नहीं है। इसके विपरीत, सेवा में उम्मीदवारों को विनियम 9 (IV) और 9 (VII) के प्रावधान के आधार पर वरीयता का अनुदान एक प्रशंसनीय उद्देश्य माना जाता है।

(2) इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए डिग्री पाठ्यक्रम में आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य के लिये केवल इस आधार पर कि विनियम 9 (VII) डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण प्रदान करता है, एक निहित समावेशन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है;

(3) यह मानते हुए कि विनियम 9 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है, दिनेश सिंह चौहान के निर्णय ने सुधीर एन बनाम केरल राज्य और गोपाल डी तीर्थानी (उपरोक्त) के निर्णयों को उचित रूप से नहीं निपटाया है।

(4) सेवा में प्रवेश के लिए एक अलग स्रोत प्रदान करने का अर्थ भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों को निम्नतर करना नहीं होगा जैसा कि योग्य उम्मीदवार एन. ई. ई. टी. परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंकों को पूरा करते और सेवा में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर प्रवेश लेते; और,

(5) मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च केंद्र में अपने निर्णय में, संविधान पीठ ने कहा है कि एक राज्य जो अपने निवासियों के कल्याण और विकास के लिए जिम्मेदार है, उसे उचित कदम उठाना राज्य का विशेषाधिकार है;

(6) डिग्री पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए केवल एक वेटेज प्रदान करना यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि कठिन परिस्थितियों में काम करते समय ऐसे उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में सेवाकालीन उम्मीदवार अर्हता प्राप्त करें।

चूंकि पहले दौर में परामर्श पहले ही हो चुका है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम आदेश आवश्यक हैं कि राज्य स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में सेवाकालीन उम्मीदवारों को प्रवेश का एक अलग स्रोत प्रदान करने से वंचित न हों।

8. दूसरी ओर, भारत संघ और एमसीआई की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि सूची III की प्रविष्टि 25 स्पष्ट रूप से सूची I की प्रविष्टि 66 प्रविष्टि के अधीन है इसलिए, अनुच्छेद 246 के तहत चिकित्सा शिक्षा पर कानून बनाने का राज्यों का अधिकार उच्च शिक्षा में मानकों के समन्वय और निर्धारण से संबंधित मामलों में संघ के प्रबल प्राधिकारी के अधीन है। विनियम 9 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। विनियम 9 (iv) सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत की दर से एन. ई. ई. टी. परीक्षा में प्राप्त अंकों के अधिकतम 30 प्रतिशत तक प्रोत्साहन प्रदान करता है। एम. सी. आई., एक विशेषज्ञ नीति निर्माता के रूप में केंद्रीय कानून के तहत गठित प्राधिकरण, ने वैधानिक विनियम तैयार किए हैं जिनके तहत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री प्रवेश में सेवाकालीन उम्मीदवारों केवल प्रोत्साहन अंक दिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार और एम. सी. आई. के सुविचारित दृष्टिकोण में, सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का

अनुदान या प्रवेश का एक अलग स्रोत चिकित्सा शिक्षा के मानकों के समन्वय और निर्धारण के लिए एम. सी. आई. के अधिकार पर सीधे प्रभाव डालेगा। दिनेश सिंह चौहान में निर्णय विशेष रूप से 2012 में संशोधित विनियमन 9 के प्रावधानों को दर्शाता है। इस स्तर पर किसी भी अंतरिम राहत के अनुदान पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय लागू रहता है। इन-सर्विस डिग्री उम्मीदवारों के लिए प्रवेश का एक अलग स्रोत निर्धारित करने से, एम.सी.आई. के प्रस्तुतिकरन में, सीधे तौर पर चिकित्सा शिक्षा में मानकों में कमी आएगी। योग्यता से समझौता किया जाएगा और सूची I की प्रविष्टि 66 के तहत मानदंडों का प्रिस्क्रिप्शन एक दुर्घटना होगी।

9. 15 फरवरी 2012 को संशोधित नियम 9 इस प्रकार हैः

"9. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया इस प्रकार होगी-

(I) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ही पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी, जिसका नाम होगा "राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा" राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा का समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र पर्यवेक्षण के तहत राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के पास निहित होगा।

(II) 3% वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की सीटें 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गति संबंधी अक्षमता वाले उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगीः

बशर्ते कि यदि इस 3 प्रतिशत कोटे में कोई भी सीट 50 से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गति संबंधी अक्षमता वाले उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहती है तब इस 3 प्रतिशत कोटे में ऐसी किसी भी खाली सीट को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल करने से पहले 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गति विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा।

और बशर्ते कि यह पूरा अभ्यास प्रत्येक मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा प्रवेश के लिए वैधानिक समय सीमा के अनुसार पूरा किया जायेगा।

(III) किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में किसी भी स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, एक उम्मीदवार के लिए उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित "स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा" में 50 वें प्रतिशत पर न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथापि, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के के उम्मीदवारों के संबंध में, न्यूनतम अंक 40 वें प्रतिशत पर होंगे। उपरोक्त खंड (II) में दिए गए निचले अंगों की गति संबंधी अक्षमता के साथ उम्मीदवारों के के संबंध में न्यूनतम अंक 45 वें प्रतिशत पर होंगे। प्रतिशत का निर्धारण स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय"राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा" में सूची में सामान्य योग्यता में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में संबंधित श्रेणियों में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो, भारतीय

चिकित्सापरिषद के परामर्श करके केंद्र सरकार अपने विवेकाधिकार पर संबंधित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित नूनतम अंको को कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे। निम्नानुसार होंगे -

(IV) चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों संबंधित श्रेणियों में सीटों का आरक्षण राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचलित लागू कानूनों के अनुसार होगा। सभी योग्य उम्मीदवारों की अखिल भारतीय योग्यता सूची के साथ-साथ पात्रों की राज्यवार योग्यता सूची उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी और उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल उक्त योग्यता सूचियों से दिया जाएगा:

(V) कोई भी उम्मीदवार जो उपरोक्त खंड (II) में निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(VI) गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में, कुल सीटों का 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) राज्य द्वारा सरकार या उनके द्वारा नियुक्त प्राधिकरण भरा जाएगा और शेष 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) सीटें संबंधित मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा स्तर पर प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर भरी जाएंगी।

(VII) स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 50 % सीटों की संख्या सरकारी सेवा में उन चिकित्सा अधिकारियों के लिए आरक्षित की जायेंगी,, जिन्होंने दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की है। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, चिकित्सा अधिकारी समय-समय पर राज्य सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिभाषित दूरस्थ और/या कठिन क्षेत्रों में दो और वर्षों के लिए सेवा करेंगे।

(VIII) विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित अधिकारी प्रवेश प्रक्रिया को इस तरह से आयोजित करेंगे कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वर्ष 2 मई से और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए 1 अगस्त तक शिक्षण शुरू हो जाए।

(IX) इस उद्देश्य के लिए, वे परिशिष्ट III में बताए गए समय-सारणी का पालन करेंगे।

(X) किसी भी शैक्षणिक सत्र के संबंध में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 31 मई और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए 30 सितंब के बाद किसी भी परिस्थिति में छात्रों का प्रवेश नहीं होगा। । उक्त तिथि के बाद को प्रवेश दिये जाने पर गया विश्वविद्यालय किसी भी छात्र को पंजीकृत नहीं करेंगे।

(XI) भारतीय चिकित्सा परिषद निर्देश दे सकती है कि प्रवेश बंद करने की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश प्राप्त करने वाले किसी भी छात्र को इस पाठ्यक्रम अध्ययन के से छुट्टी दे दी जाए, या ऐसे छात्र को दी गई कोई भी चिकित्सा योग्यता भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता नहीं

होगी। वह संस्थान जो इसके लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, वह भी ऐसी कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा जो हो सके। एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित किया जाएगी जिसमें आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए अपनी स्वीकृत प्रवेश क्षमता से किए गए इस तरह के प्रवेश की सीमा के बराबर सीटों का समर्पण शामिल है। (पृष्ठों पर आईडी 764-766)"

इस प्रकार सूची I के प्रविष्टि 66 प्रदान करती हैः

"66. उच्च शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के लिए संस्थान मानकों का समन्वय और निर्धारण।“

इस प्रकार सूची III प्रविष्टि 25 प्रदान करती हैः

"25. सूची I की प्रविष्टियों 63, 64, 65 और 66 के प्रावधानों के अधीन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा,; श्रम का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।“

10. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर (उपरोक्त) में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि "मानकों का समन्वय और निर्धारण" अभिव्यक्ति का अर्थ मानकों को निर्धारित करना है। इसलिए, जब उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानकों को निर्धारित करने की बात आती है, तो विशेष अधिकार क्षेत्र संघ को दिया जाता है। इस प्रका संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने कहाः

"102. प्रवेश सहित अधिकांश शैक्षिक गतिविधियों के दो पहलू हैं: पहला शिक्षा के न्यूनतम मानकों को अपनाने और स्थापित करने से संबंधित है। न्यूनतम मानक निर्धारित करने का उद्देश्य पूरे देश में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की क्षमता और गुणवत्ता का एक मानक प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित शिक्षा के मानकों का समन्वय मानकों का निर्धारण के लिये बहुत ही सहायक है। राष्ट्र की विशाल विविधता को महसूस करते हुए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर, उच्च उत्कृष्टता वाले संस्थानों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण शिक्षा के स्तर में उतार-चढ़ाव आया उसे देखते हुए, विभिन्न स्तरों पर, विशेष रूप से अनुसंधान संस्थानों, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के स्तर पर शिक्षा के बुनियादी न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना और निर्धारित करना वांछनीय माना जाता था। इस प्रकार, स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए, राष्ट्र के लिए एक समान न्यूनतम मानक निर्धारित करना आवश्यक था। नतीजतन, संविधान निर्माताओं ने अनुसंधान, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा के समान मानकों को

बनाए रखने के उद्देश्य से सूची I प्रविष्टि 66 का प्रावधान किया।“

(आईडी पृष्ठ 430 पर)

संसद द्वारा निर्धारित शिक्षा के मानकों को लागू करने और शिक्षा की पूरी गतिविधि को विनियमित करने के लिए इस प्रकार निर्धारित मानकों को लागू करना आवश्यक है। सूची I की प्रविष्टि 66 और सूची III की प्रविष्टि 25 के बीच संतुलन को पहले के संविधान पीठ के फैसलों की समीक्षा पर संक्षेप में तैयार किया गया है, इस प्रकारः

"104 ..... गुजरात विश्वविद्यालय में [गुजरात विश्वविद्यालय बनाम कृष्ण रंगनाथ मुधोलकर, ए. आई. आर 1963 एस. सी. 703: 1963 पूरक (1) एस. सी. आर. 112], पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ ने सूची I प्रविष्टि 66 के संदर्भ में सूची II प्रविष्टि 11 (जो अब सूची III प्रविष्टि 25 है) के दायरे की जांच की। यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिक्षा के संबंध में कानून बनाने की राज्य की शक्ति जिस हद तक संसद को सौंपी गई है, उसे प्रतिबंधित होना माना जाता है। मानकों का समन्वय और निर्धारण सूची I के दायरे में था और उक्त विषय पर राज्य की शक्ति संघ की शक्ति के अधीन थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दोनों प्रविष्टियाँ कुछ हद तक अतिव्यापी हैं और अतिव्यापी होने की सीमा तक सूची I प्रविष्टि 66 द्वारा प्रदत्त शक्ति को राज्य की सत्ता पर हावी होना चाहिए। राज्य विधान की वैधता इस बात पर

निर्भर करती है कि क्या यह "मानकों के समन्वय या निर्धारण" को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, भले ही इसमेन संघ के कानून के अभाव हो। आर. चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य [आर. चित्रलेखा बनाम। मैसूर राज्य, ए. आई. आर 1964 एस. सी. 1823: (1964) 6 एस. सी. आर. 368], में उसी मुद्दे पर फिर से विचार किया गया था। यह देखा गया कि यदि केंद्रीय क्षेत्र को मिटा देने या कम करने की दिशा में राज्य के कानून का प्रभाव भारी है या विनाशकारी है तो, यह गिरा दिया जा सकता है। राज्य टी. एन. राज्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड अनुसंधान संस्थान [स्टेट ऑफ टी. एन. बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड अनुसंधान संस्थान, (1995) 4 एस. सी. सी. 104: 1 एससीईसी 682], में यह देखा गया था कि इस हद तक कि राज्य का कानून प्रविष्टि 25 के तहत केंद्रीय कानून के साथ टकराव में है, यह अमान्य और निष्क्रिय होगा । उसी प्रभाव के लिए प्रीति श्रीवास्तव [प्रीति श्रीवास्तव बनाम एम. पी. राज्य, (1999) 7 एस. सी. सी. 120: 1 एस.सी.ई.सी. 742] और महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय [महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षा शास्त्र महाविद्यालय, (2006) 9 एस. सी. सी. 1: 5 एससीईसी 637] में लिया गया दृष्टिकोण है। यद्यपि एम. पी. राज्य बनाम निवेदिता जैन [एम. पी. बनाम राज्य निवेदिता जैन (1981) 4

एस. सी. सी. 296] और अजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य [अजय कुमार सिंह बनाम। बिहार राज्य, (1994) 4 एस. सी. सी. 401] में इस प्रभाव के लिए लिया गया दृष्टिकोण कि सूची I प्रविष्टि 66 द्वारा आच्छादित प्रवेश मानक केवल प्रवेश होने के बाद ही लागू किये जा सकते थे, प्रीति श्रीवास्तव में [प्रीति श्रीवास्तव बनाम। एम. पी. राज्य, (1999) 7 एससीसी 120: 1 एस. सी. ई. सी. 742], में नहीं माना गया था, यह अभिनिर्धारित नहीं किया गया था कि सूची I द्वारा प्रवेश सम्पूर्ण सरगम को शामिल किया गया था जैसा कि भारती विद्यापीठ में गलत तरीके से माना गया थाई [भारती विद्यापीठ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) 11 एससीसी 755: 2 एससीईसी 535]। (पेज 431 पर आईडी)

संविधान पीठ ने कहा कि जबकि सूची III की प्रविष्टि 25 सूची I में प्रविष्टि 66 के अधीन है, प्रवेश के पूरे सरगम को कानूनों के अवलोकन से अलग नहीं किया गया है। हालाँकि, सूची III के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग प्रविष्टि 25 को प्रवेश के लिए संदर्भित केंद्रीय कानून के अधीन होना चाहिए।“

12. विनियम 9 के प्रावधान दिनेश सिन्ह चौहान (उपरोक्त) में तीन सदस्यीय पीठ द्वारा अर्थ लगाया है । इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि निर्णय ने विनियमन 9 के संशोधित प्रावधानों का अर्थ लगाया है। विनियम 9 ने इसे चिकित्सा

पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में एक स्व-निहित कोड माना है। इस संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया हैः

"24. अब तक, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विनियमन 9 एक स्व-निहित कोड है जिसका पालन चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में किया जाना है । यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि राज्य के पास ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो केंद्रीय कानून और उसके तहत बनाए गए विनियमों द्वारा प्रतिपादित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है, क्योंकि यह संविधान की अनुसूची VII सूची I प्रविष्टि 66 के भीतर आने वाला विषय है (प्रीति श्रीवास्तव बनाम एम. पी. राज्य देखे [प्रीति श्रीवास्तव बनाम एम. पी. राज्य, (1999) 7 एस. सी. सी. 120: 1 एससीईसी 742])। स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर केंद्रीय कानून और विनियम प्रबल होने चाहिए। (पृष्ठ 766 पर आईडी)

दिनेश सिंह चौहान में कानून का उपरोक्त कथन उन सिद्धांतों के अनुरूप है जिनकी पुष्टि मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर की संविधान पीठ ने की है। संदर्भ आदेश में कहा गया है कि मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्णय दिनेश सिंह चौहान के फैसले के बाद रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया था। हमारे विचार में, तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का मूल आधार उन सिद्धांतों के अनुरूप है जो संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

12. विनियम 9 (IV) की व्याख्या करते हुए, दिनेश सिंह चौहान का मानना है कि प्रारंभिक वाक्य में उल्लिखित आरक्षण स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए संवैधानिक आरक्षण है, न कि सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए: नियम 9 (IV) में प्रावधान की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया हैः

> "25.4 ..... हालाँकि, इस प्रावधान में एक परंतुक है। यह भविष्यवाणी करता है कि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण की सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने में, राज्य के दूरस्थ या कठिन क्षेत्र में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एन. ई. ई. टी. में प्राप्त अंकों के 10 प्रतिशत अधिकतम 30 प्रतिशत तक की दर से सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रोत्साहन के रूप में अंकों में वेटेज हो सकता है। यह प्रावधान भले ही उदारतापूर्वक पढ़ा जाए, सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि केवल सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों (जिन्होंने राज्य में अधिसूचित दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में सेवा की है) के वर्ग के लिए निर्दिष्ट प्रोत्साहन अंकों के रूप में वेटेज देने का प्रावधान करता है। (पृष्ठ पर आई. डी. 767)
>
> परंतुक की व्याख्या स्पष्ट रूप से उपयोग किए गए शब्दों के स्वाभाविक और सामान्य रूप का अनुसरण करती है। नियम 9 (IV)

का परंतुक स्नातकोत्तर में सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नहीं बल्कि प्रोत्साहन अंक प्रदान करता है। दिनेश सिंह चौहान ने मौखिक रूप से इस दलील को खारिज कर दिया है कि सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए कोई स्पष्ट निषेध नहीं है और इसलिए यह राज्य सरकारों को उन्हें प्रदान करने के लिए जारी करने की अनुमति होगी:

"27 ..... चूंकि स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को प्रतिबंधित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए यह तर्क दिया गया कि इस तरह के प्रावधान राज्य सरकार द्वारा आरक्षण कानून में अनुज्ञेय नहीं है। इसके अलावा, इस न्यायालय के उदाहरण हैं जो यह सुझाव देते हैं कि इस तरह की व्यवस्था प्रवेश के एक अलग चैनल के रूप में अनुमत है। यह निर्णय हमें प्रभावित नहीं करता है। सबसे पहले, लागू किये गये निर्णयों में प्रासंगिक समय पर लागू नियमों द्वारा शासित प्रवेश प्रक्रिया से सम्बंधित प्रावधानों पर विचार किया गया है। वतमान मामले में प्रवेश प्रक्रिया उन नियमों द्वारा शासित होती है जो शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 से लागू हुए हैं। यह विनियम एक स्व-निहित सन्हिता है। इस विनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दूर-दूर तक संकेत दे सके कि सेवारत उम्मीदवारों को एक अलग चैनल प्रदान किया जाना चाहिये, कम से कम स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों में।

हालाँकि, इसके विपरीत, 50 प्रतिशत सीटें सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर "डिप्लोमा" पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हैं, जैसा कि खंड (II) से स्पष्ट है। यदि विनियमन का उद्देश्य स्नातकोत्तर "डिग्री" पाठ्यक्रमों के संबंध में भी सेवा उम्मीदवारों के लिए एक समान अलग चैनल का इरादा था, तो उस स्थिति को विनियमन 9 में ही स्पष्ट कर दिया गया होता।" (आईडी 767-768 पृष्ठ पर)"

13. निर्णय में देखा गया है कि विनियम 9 तैयार करने में, सरकारी सेवा में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए डिप्लोमा सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहाँ विधायिका के प्रतिनिधियों का आरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य था, वहाँ विनियम 9 (VII) में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर, स्नातकोत्तर डिग्री सीटों के लिए, विनियमन 9 (IV) में केवल प्रोत्साहन अंकों का प्रिस्क्रिप्शन है। यह देखते हुए कि ये नियम एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा बनाए गए हैं, यह इस प्रकार माना गया हैः

"35. जैसा कि ऊपर कहा गया है, विनियमों को एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा पिछले अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है और इसमें राज्य के अधिसूचित दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में सेवा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सेवाओं और अनुभव की गणना करने की आवश्यकता भी शामिल है। परंतुक में जिन उम्मीदवारों ने राज्य में अधिसूचित दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में काम किया है ऐसे सेवा में रहने

वालों को प्रोत्साहन अंक देने का उपाय निर्धारित किया गया है। इसे उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए एक गुणात्मक कारक कहा जा सकता है। यहाँ तक कि परंतुक में सेवा में योग्य उम्मीदवारों की योग्यता की गणना करने के लिए मात्रात्मक कारक का उल्लेख किया गया है। इसमें दूरदराज और/या कठिन क्षेत्रों में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए प्राप्त 10 प्रतिशत अंकों पर एन. ई. ई. टी. में प्राप्त अंकों के 30 प्रतिशत तक प्रोत्साहन अंक देने की परिकल्पना की गई है। यह उम्मीदवार द्वारा एन. ई. ई. टी. में प्राप्त अंकों को प्रोत्साहन अंकों से जोड़ने की एक वस्तुनिष्ठ विधि है।" (पृष्ठ 772 पर आईडी)

यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर अदालत ने अन्य निर्णयों में डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम एम. पी. राज्य के साथ-साथ में लिए गए तीर्थानी, एम्स छात्र संघ और सुधीर एन (सुप्रा) मामले में संविधान पीठ के फैसले पर उचित ध्यान दिया है।"

14. दिनेश सिंह चौहान का फैसला मैदान में है। यह विनियम 9 (IV) के निर्माण पर आधारित है, जिसे कम से कम वर्तमान चरण में दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उस निर्णय में जो सिद्धांत अपनाया गया है वह उस प्रधानता के अनुरूप है जिसे संविधान द्वारा सूची I की प्रविष्टि 66 के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह सूची III की प्रविष्टि 25 में "विषय" शब्दों का स्पष्ट इरादा है। वर्तमान चरण में किसी भी अंतरिम राहत का अनुदान एक अनिवार्य अंतिम आदेश के बराबर होगा जो माना नहीं

जा सकता। एम.सी.आई., एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में, सैद्धांतिक आधार पर आगे बढ़ा है। इस स्तर पर विनियमन 9 (IV) में पढ़ने का कोई भी प्रयास, प्रवेश का एक अलग स्रोत या एक डिग्री पाठ्यक्रम में सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण केंद्रीय कानून के तहत नियामक शक्तियों के प्रयोगऔर सूची I की प्रविष्टि 66 पर अतिक्रमण करेगा।

15. इन कारणों से, हम अंतरिम राहत देने में असमर्थ हैं, जिसका आग्रह अपीलार्थियों की ओर से किया गया है। तदनुसार राहत देने से इनकार कर दिया जाता है। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि जो परामर्श होता है, वह अंततः संदर्भ के परिणाम से पालन करेगागा। तदनुसार, 2018 की आई. ए. सं. 33686 का निस्तारण किया गया है।

कल्पना के. त्रिपाठी

आई.ए. का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता बृजेश कुमार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।